



UnderStand UPSC
What we UnderStand, We Conquer

UPPCS MCA MASTER CURRENT AFFAIRS

JAN 2026

Spotlight

- Wings India 2026
- Pax Silica
- World's Fourth Largest Economy
- India's First AI-Powered University
- UP's First Zero Fresh Waste Dump City
- Prelims Panacea



Satyam Jain

Teacher / Founder - UnderStand UPSC
3 UPSC CSE Interviews
Mentored 300+ Rankers including AIR-1



Call For More Info
8377072252



Ground floor, 11B, Bada Bazar Road, Old Rajender Nagar, New Delhi - 110060



understand.upsc



UnderStandUPSC.com



: UnderStand UPSC

राष्ट्रीय चर्चा

विंग्स इंडिया 2026

खबरों में क्यों: एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य इस शताब्दी के मध्य तक भारत को विमानन के वैश्विक केंद्र में बदलना है।

मुख्य विशेषताएं:

- विमानन मंत्रालय, हवाई अड्डा प्राधिकरण और एक उद्योग निकाय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया कि भारत 2047 तक **चार सौ से अधिक** हवाई अड्डों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।
- एयर इंडिया ने बोइंग से तीस और विमानों का ऑर्डर दिया, जिससे उसके कुल ऑर्डर की संख्या छह सौ हो गई, जबकि एक सार्वजनिक क्षेत्र की एयरोस्पेस फर्म ने एक अन्य ऑपरेटर को दस नए हेलीकॉप्टर की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की।
- गुजरात को राज्य में विमानन को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना और उत्तराखंड के साथ संयुक्त रूप से पुरस्कार मिला। इस कार्यक्रम में फ्लाईंग टैक्सी और ड्रोन जैसी नई तकनीकों पर भी चर्चा हुई।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- आयोजक: नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और FICCI
- दीर्घकालीन लक्ष्य का उल्लेख किया गया: 2047 तक चार सौ से अधिक हवाई अड्डे।
- उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर चर्चा: इलेक्ट्रिक फ्लाईंग टैक्सी (eVTOL)
- पुरस्कार श्रेणी में गुजरात, तेलंगाना और उत्तराखंड ने संयुक्त रूप से विजय हासिल की: विमानन को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य।
- छोटे शहरों तक हवाई यात्रा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई क्षेत्रीय संपर्क योजना को UDAN (उड़ें देश का आम नागरिक) कहा जाता है।

उदय, आधार का नया चेहरा

खबरों में क्यों: विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आम लोगों को आधार से संबंधित जानकारी को अधिक सुगमता से समझने में मदद करने के लिए **उदय** नामक एक शुभंकर पेश किया है।

मुख्य विशेषताएं:

- उदय एक चैटबॉट और विजुअल हेल्पर की तरह काम करता है, जो आधार विवरण को अपडेट करने का तरीका, प्रमाणीकरण कैसे काम करता है, सेवा शुल्क और ऑफ़लाइन पहचान सत्यापित करने का तरीका जैसी चीजों को समझाता है।
- इस किरदार का चयन सरकार की नागरिक सहभागिता वेबसाइट के माध्यम से आयोजित एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता के जरिए किया गया था, जिसमें छात्रों, पेशेवरों और डिजाइनरों से सैकड़ों प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।
- डिजाइन प्रतियोगिता में **केरल** के एक प्रतिभागी ने जीत हासिल की, जबकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के प्रतिभागियों ने अगले दो स्थान प्राप्त किए।
- शुभंकर का नाम रखने के लिए आयोजित एक अलग प्रतियोगिता भोपाल के एक प्रतिभागी ने जीती। इसका मुख्य उद्देश्य आधार कार्ड को लेकर भ्रम को कम करना और इसके सुरक्षित उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- जिम्मेदार निकाय: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)
- चयन प्रक्रिया: MyGov प्लेटफॉर्म पर आयोजित एक सार्वजनिक प्रतियोगिता के माध्यम से।
- शुभंकर की भूमिका: आधार सेवाओं के लिए चैटबॉट और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है
- पृष्ठभूमि: प्राधिकरण की स्थापना 2009 में हुई थी और आधार अधिनियम 2016 में पारित किया गया था।
- UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन कार्य करता है।

- आधार एक बारह अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो जैव-माप और जनसांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित है।

लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतराष्ट्रीय सम्मेलन

खबरों में क्यों: चुनाव आयोग ने दिल्ली में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जो इसी के साथ आयोजित किया गया था।

मुख्य विशेषताएं:

- आयोग के समर्पित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित तीन दिवसीय सम्मेलन में अन्य देशों के सौ से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- प्रमुख परिणामों में चुनाव संबंधी सेवाओं के लिए एक एकल पहुंच बिंदु के रूप में काम करने वाले एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ, मतदाता सूचियों की सटीकता और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित चुनाव निकायों के बीच एक संयुक्त घोषणा और चुनाव प्रबंधन में क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए **नामीबिया** के साथ एक समझौता शामिल है।
- इसके अलावा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस सोलहवीं बार भारतीय लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका पर केंद्रित विषय के तहत मनाया गया, जिसमें प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम उपयोग और मतदाता जागरूकता प्रयासों के लिए पुरस्कार दिए गए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- आयोजक: भारतीय चुनाव आयोग, अपने प्रशिक्षण संस्थान, IIIDEM (इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट) के माध्यम से।
- नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया: ECINET
- सम्मेलन का परिणामी दस्तावेज: जिसे दिल्ली घोषणा के नाम से जाना जाता है
- सोलहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय: भारतीय लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका पर केंद्रित।
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, जो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना का दिन है (स्थापना 1950)।

सोमनाथ मंदिर का स्वाभिमान समारोह

खबरों में क्यों: भगवान शिव को समर्पित बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर, एक ऐतिहासिक आक्रमण के हजार साल पूरे होने और मंदिर के जीर्णोद्धार के पचहत्तर साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों के कारण खबरों में था।

मुख्य विशेषताएं:

- गुजरात के तट पर स्थित यह मंदिर लगभग पंद्रह सौ वर्षों में सत्रह बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया जा चुका है, जिसमें कई ऐतिहासिक आक्रमणकारियों के हमले भी शामिल हैं।
- स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसका आधुनिक पुनर्निर्माण किया गया, जो औपचारिक रूप से पूरा हुआ और 1950 के दशक की शुरुआत में भारत के पहले राष्ट्रपति की उपस्थिति में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया।
- हाल ही में हुए समारोहों में सैकड़ों धार्मिक हस्तियों की उपस्थिति, बहत्तर घंटे तक लगातार मंत्रोच्चार, मंदिर की रक्षा करने वालों को सम्मान देने के लिए सौ से अधिक घोड़ों वाली एक प्रतीकात्मक शोभायात्रा और बड़े पैमाने पर ड्रोन प्रदर्शन शामिल थे।
- प्रधानमंत्री ने स्वयं उपस्थित होकर औपचारिक दीप प्रज्वलित किया और मंदिर को भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बताया।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- भगवान शिव से जुड़े बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक।
- स्थान: वेरावल के पास, प्रभास पाटन, गुजरात के तटीय क्षेत्र में
- मंदिर के आधुनिक पुनर्निर्माण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है।
- ऐतिहासिक रूप से इस मंदिर को सत्रह बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया है।
- यहां जिस ऐतिहासिक आक्रमणकारी का जिक्र किया जा रहा है, वह गजनी का महमूद है, जिसने 1026 ईस्वी में मंदिर पर हमला किया था।
- स्वतंत्रता के बाद मंदिर के पुनः उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे।

भारत ऊर्जा सप्ताह (India Energy Week) 2026

खबरों में क्यों: गोवा ने इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण की मेजबानी की, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव में भारत को एक अग्रणी अभिकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना था।

मुख्य विशेषताएं:

- पेट्रोलियम कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक उद्योग निकाय और एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन फर्म द्वारा **पेट्रोलियम मंत्रालय** के मार्गदर्शन में संयुक्त रूप से आयोजित इस सम्मेलन में एक सौ बीस से अधिक देशों के प्रतिनिधि, सैकड़ों प्रदर्शक और ऊर्जा क्षेत्र के दसियों हज़ार पेशेवर एक साथ आए।
- इस कार्यक्रम में हुई चर्चाओं में ऊर्जा सुरक्षा, कार्बन उत्सर्जन में कटौती और निवेश के नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें हाइड्रोजन, जैव ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए अलग-अलग क्षेत्र स्थापित किए गए थे।
- एक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी ने ड्रोन और स्कूटर सहित नए उत्पादों का प्रदर्शन किया, जो दोनों हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- संबंधित मंत्रालय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- आयोजक: फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज और dmg इवेंट्स
- यह इस आयोजन का चौथा संस्करण था।
- मुख्य क्षेत्र: हाइड्रोजन, जैव ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता
- संबंधित राष्ट्रीय मिशन: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था।
- उल्लिखित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)
- जैव ईंधन से संबंधित प्रमुख योजना: SATAT (वहनीय परिवहन की दिशा में सतत वैकल्पिक योजना)

भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया

खबरों में क्यों: भारत ने कर्तव्य पथ पर अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, जिसका विषय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रखा गया था।

मुख्य विशेषताएं:

- राष्ट्रपति ने समारोह का नेतृत्व किया, जिसमें यूरोपीय परिषद के प्रमुख **एंटोनियो कोस्टा** और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष **उर्सुला वॉन डेर लेयेन** मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यह पहली बार था जब यूरोपीय संघ की किसी सैन्य इकाई ने यूरोप के बाहर आयोजित परेड में भाग लिया।
- परेड में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय विभागों की लगभग तीस झांकियां शामिल थीं, साथ ही तीनों सेनाओं द्वारा हाल ही में हुए एक सैन्य अभियान के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें मिसाइल प्रणाली और एक स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर शामिल थे।
- पहली बार युद्धक्षेत्र की संरचना को दर्शाने वाली एक नई परेड का प्रदर्शन किया गया। एक वायुसेना अधिकारी को वीरता के लिए देश का सर्वोच्च शांतिकालीन पुरस्कार प्राप्त हुआ, और समारोह का समापन उनतीस विमानों की फ्लाईपास्ट के साथ हुआ।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- इस वर्ष का विषय: वंदे मातरम के डेढ़ सौ वर्ष
- परेड के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार: अशोक चक्र
- उल्लेखनीय घटना: यूरोपीय संघ की एक सैन्य इकाई ने पहली बार यूरोप के बाहर किसी परेड में भाग लिया।
- भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिससे भारत को गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्राप्त हुई।
- वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और इसे 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था।

HAL ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली उड़ान पूरी की

खबरों में क्यों: नागरिक उड्डयन मंत्री ने बेंगलुरु में HAL के नए ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर खाना किया, जो भारत के हेलीकॉप्टर कार्यक्रम के लिए एक बड़ा कदम है।

मुख्य विशेषताएं:

- ध्रुव NG एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर का नागरिक संस्करण है जिसे पहली बार पिछले साल एयरो इंडिया में जनता के सामने प्रदर्शित किया गया था।
- यह एक हल्का, दो इंजन वाला, बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है जो लगभग साढ़े पांच टन भार ले जा सकता है, और इसमें आधुनिक ग्लास कॉकपिट और कंपन को कम करने वाली प्रणालियाँ लगी हैं जिससे उड़ान सुगम होती है।
- यह लगभग 285 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और इसमें चौदह लोगों के बैठने की व्यवस्था हो सकती है।
- एयरलाइंस और ऑपरेटर उड़ान के घंटों या प्रदर्शन के आधार पर लचीले भुगतान मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। अधिकारी इसे समान आकार के आयातित हेलीकॉप्टरों की तुलना में एक सस्ता और उच्च प्रदर्शन वाला विकल्प मानते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- बेंगलुरु स्थित मुख्यालय वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा निर्मित।
- यह दो शक्ति इंजनों पर चलता है, जिन्हें HAL और फ्रांस की सैफरान ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।
- बेंगलुरु के येलाहांका वायुसेना स्टेशन में आयोजित एयरो इंडिया में इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था।
- यह ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर का नागरिक संस्करण है।
- HAL रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

सांख्यिकी मंत्रालय के लिए नया लोगो और शुभंकर

खबरों में क्यों: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनी सार्वजनिक छवि को आधुनिक बनाने के प्रयास के तहत एक नया लोगो और शुभंकर जारी किया है।

मुख्य विशेषताएं:

- नए लोगो में "विकास के लिए डेटा" का संदेश निहित है। इसमें अशोक चक्र का उपयोग ईमानदारी और सुशासन के प्रतीक के रूप में किया गया है, और रुपये के प्रतीक का उपयोग आर्थिक नियोजन के लिए आंकड़ों के महत्व को दर्शाने के लिए किया गया है।
- इसके रंग, जो राष्ट्रीय ध्वज के रंगों के साथ-साथ गहरे नीले रंग से लिए गए हैं, विकास, सत्य, स्थिरता, स्थायित्व और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- लोगो के साथ-साथ, मंत्रालय ने सांख्यिकी नामक एक शुभंकर भी पेश किया, जिसे आम नागरिकों के लिए आंकड़ों को सुलभ बनाने और सर्वेक्षणों, जागरूकता अभियानों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- मंत्रालय: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
- नए शुभंकर का नाम: सांख्यिकी
- नए लोगो का टैगलाइन: विकास के लिए डेटा
- प्रयुक्त प्रतीक: अशोक चक्र और रुपये का चिह्न
- MoSPI, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) जैसे प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित करता है।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) को संकलित करने की जिम्मेदारी भी MoSPI की है।

युवा नेताओं के संवाद का दूसरा संस्करण

खबरों में क्यों: युवाओं को सार्वजनिक जीवन में लाने के उद्देश्य से आयोजित संवाद का दूसरा संस्करण भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जो राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर समाप्त हुआ।

मुख्य विशेषताएं:

- यह आयोजन प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक पृष्ठभूमि से न आने वाले एक लाख युवाओं को राजनीति और सार्वजनिक सेवा में शामिल करना है।
- इस वर्ष लगभग तीन हजार युवा नेताओं ने भाग लिया, जिनका चयन ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, निबंध प्रतियोगिता और राज्य स्तरीय प्रस्तुतियों के माध्यम से किया गया था। इस बार डिजाइन थिंकिंग और राष्ट्रीय विकास के लिए प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया।
- इसका व्यापक लक्ष्य युवाओं के विचारों को सीधे सरकार के वरिष्ठ नेतृत्व तक पहुंचाना है, ताकि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाया जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- स्थान: भारत मंडपम, नई दिल्ली
- यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद की जयंती (12 जनवरी) यानी राष्ट्रीय युवा दिवस पर समाप्त होगा।
- प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित व्यापक लक्ष्य: राजनीतिक पृष्ठभूमि के बिना एक लाख युवाओं को शामिल करना।
- संदर्भित दीर्घकालिक राष्ट्रीय परिकल्पना: 2047 तक एक विकसित भारत (विकसित भारत @2047), जो भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी का वर्ष है।
- स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था और उन्होंने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
- भारत मंडपम, जो इस आयोजन का केंद्र है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान परिसर का हिस्सा है और इसने 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी।

NHAI ने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए

खबरों में क्यों: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक ही दिन में छह लेन वाले राजमार्ग पर सड़क की सतह बनाने वाली सामग्री बिछाने के लिए दो बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया है, जो इस आकार के राजमार्ग के लिए दुनिया में कहीं भी पहली बार हुआ है।

मुख्य विशेषताएं:

- ये रिकॉर्ड कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले राजमार्ग के एक हिस्से पर बनाए गए, जहां चौबीस घंटे के भीतर सड़क निर्माण सामग्री की असामान्य रूप से बड़ी मात्रा बिछाई गई।
- तीन सौ किलोमीटर से अधिक लंबा यह कॉरिडोर व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ दोनों राज्यों के बीच यात्रा के समय को कम करने की उम्मीद है।
- बाद में उसी खंड पर दो और रिकॉर्ड बनाए गए, जिससे इस एक परियोजना पर कुल रिकॉर्डों की संख्या चार हो गई, जो भारत की बढ़ती सड़क निर्माण क्षमता का संकेत है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- गलियारा शामिल: बेंगलुरु-कडप्पा-विजयवाड़ा तक आर्थिक गलियारा
- यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को जोड़ता है।
- इस गलियारे पर कुल चार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए गए।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1988 में पारित एक विधेयक के तहत की गई थी।
- NHAI सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- NHAI भारतमाला परियोजना को लागू करने के लिए भी जिम्मेदार है, जो एक प्रमुख राजमार्ग विकास कार्यक्रम है।

भारतीय भाषाओं पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

खबरों में क्यों: भारत के उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए देश की अनेक भाषाओं को इसकी सांस्कृतिक पहचान का संरक्षक बताया।

मुख्य विशेषताएं:

- सम्मेलन में हुई चर्चा का केंद्र बिंदु न केवल रोजमर्रा की बातचीत में बल्कि सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों और कक्षाओं में भी भारतीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना था, और यह भी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता देश की कई क्षेत्रीय भाषाओं के बीच अनुवाद करने में कैसे मदद कर सकती है।
- यह व्यापक शिक्षा नीति के उस लक्ष्य से जुड़ा हुआ है जिसके तहत छोटे बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें।
- उपराष्ट्रपति ने टिप्पणी की कि भाषाएँ किसी समुदाय के इतिहास और मूल्यों को अपने साथ लिए होती हैं, और वे संचार के साधारण साधनों से कहीं अधिक हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया
- भारत (राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी)
- चर्चा की गई तकनीक: क्षेत्रीय भाषाओं के बीच अनुवाद के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता
- संबंधित शिक्षा नीति लक्ष्य: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण।
- संबंधित सरकारी पहल: भाषिणी भाषा मंच (संदर्भ प्रविष्टि 21)
- संविधान के सत्रहवें भाग (अनुच्छेद 343 से 351) में आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है।
- अनुच्छेद 343 के अनुसार, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी, अंग्रेजी के साथ-साथ संघ की आधिकारिक भाषा है।

द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन

खबरों में क्यों: भारत ने दिल्ली में बौद्ध नेताओं के वैश्विक सम्मेलन के दूसरे संस्करण की मेजबानी की, जिसका केंद्र बिंदु साझा ज्ञान और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व था।

मुख्य विशेषताएं:

- संस्कृति मंत्रालय** और एक अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्था द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस शिखर सम्मेलन में वरिष्ठ भिक्षुओं और विद्वानों सहित विदेशों से लगभग दो सौ प्रतिनिधि एक साथ आए, और कुल उपस्थिति आठ सौ से अधिक लोगों की रही।
- सत्रों में बौद्ध दर्शन में सामाजिक सद्भाव और आजीविका से लेकर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और मठवासी समुदाय की भूमिका जैसे विषयों को शामिल किया गया।
- इस आयोजन में बौद्ध शिक्षाओं और भाषा को समझने के लिए प्रशिक्षित एक नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण का परिचय कराया गया। इस प्रकार का पहला शिखर सम्मेलन कुछ वर्ष पहले **दिल्ली** में आयोजित किया गया था।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- आयोजक: संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC)
- स्थान: भारत मंडपम, नई दिल्ली
- शिखर सम्मेलन में नया AI टूल लॉन्च किया गया: इसका नाम नोर्बू रखा गया है।
- इस श्रृंखला का पहला शिखर सम्मेलन इससे पहले (2023 में) नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का मुख्यालय **नई दिल्ली** में है और यह वैश्विक स्तर पर बौद्ध विरासत को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का 53वां संस्करण

खबरों में क्यों: इस वर्ष के नए दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के तीसरे संस्करण में भारतीय सैन्य इतिहास पर केंद्रित विषय और पहली बार सभी के लिए निःशुल्क प्रवेश की बदौलत रिकॉर्ड संख्या में आगंतुक आए।

मुख्य विशेषताएं:

- भारत मंडपम में राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस मेले का विषय भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास और योगदान को समर्पित था, जिसमें सैकड़ों पुस्तकों के साथ-साथ टैंक, युद्धपोत और लड़ाकू विमानों जैसे स्वदेशी रक्षा उपकरणों के मॉडल भी प्रदर्शित किए गए थे।
- पहली बार प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क करने से मेले के दौरान 20 लाख से अधिक आगंतुक आए। कतर को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था, जबकि स्पेन को विशेष रूप से लक्षित देश के रूप में प्रदर्शित किया गया था। अन्य आकर्षणों में हजारों निःशुल्क ई-पुस्तकों वाली एक डिजिटल लाइब्रेरी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और बच्चों की गतिविधियों के लिए एक समर्पित क्षेत्र शामिल थे।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- आयोजक: शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट (NBT)
- स्थान: भारत मंडपम, नई दिल्ली
- विशिष्ट अतिथि देश: कतर; लक्षित देश: स्पेन
- पुस्तक पठन को बढ़ावा देने और सस्ती पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए 1957 में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी।

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक भांग की खेती की अनुमति दी गई

खबरों में क्यों: हिमाचल प्रदेश ने "ग्रीन टू गोल्ड" नामक एक योजना के तहत औद्योगिक भांग की विनियमित खेती को वैधानिक मान्यता दे दी है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को बढ़ावा देना है।

मुख्य विशेषताएं:

- अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अनुमति केवल औद्योगिक और औषधीय उपयोग के लिए है, और पौधे में मादक यौगिक की मात्रा बहुत कम सीमा से नीचे रहनी चाहिए, साथ ही खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले बीजों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए।
- भांग के हजारों संभावित उपयोग हैं, वस्त्रों से लेकर कागज और ईंधन तक, और राज्य को उम्मीद है कि इससे प्रति वर्ष आठ सौ से एक हजार करोड़ रुपये की आय हो सकती है।
- इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, कीटनाशकों की जरूरत नहीं होती है, और अधिकांश फसलों के विपरीत, यह बंदरों या आवारा जानवरों से क्षतिग्रस्त नहीं होती है, जो उन किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है जिनकी फसलें अक्सर इनके कारण बर्बाद हो जाती हैं।
- खेतों की निगरानी ड्रोन और डिजिटल मानचित्रों का उपयोग करके की जाएगी, और लाइसेंस अनिवार्य होंगे।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- मादक यौगिक का अधिकतम अनुमत स्तर: शून्य दशमलव तीन प्रतिशत से कम
- लागू विधि: स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
- अनुमानित वार्षिक राजस्व: आठ सौ से एक हजार करोड़ रुपये
- निगरानी उपकरण: ड्रोन और डिजिटल मैपिंग, साथ ही अनिवार्य लाइसेंस
- यहां जिस मादक यौगिक का उल्लेख किया गया है वह टेट्राहाइड्रोकेनाबिनोल (THC) है।
- उत्तराखंड उन पहले राज्यों में से था जिन्होंने औद्योगिक भांग की खेती को वैध बनाया, जिससे हिमाचल प्रदेश उन कुछ राज्यों में से एक बन गया जिन्होंने औपचारिक रूप से इसकी अनुमति दी है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने ग्रंथ कुटीर पुस्तकालय का उद्घाटन किया

खबरों में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद स्थित अपने आवास पर धर्मग्रंथों के एक नए पुस्तकालय का उद्घाटन किया, जो भारत की साहित्यिक परंपराओं को संरक्षित करने के प्रयासों का एक हिस्सा है।

मुख्य विशेषताएं:

- **ग्रंथ कुटीर** के नाम से जानी जाने वाली यह पुस्तकालय, औपनिवेशिक काल के साहित्य के उस संग्रह की जगह लेती है जो पहले इस स्थान पर रखा गया था।
- इसमें अब वेद, पुराण और उपनिषद जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों के साथ-साथ ताड़ के पत्ते, छाल और कपड़े जैसी सामग्रियों पर लिखी गई पचास से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियां भी रखी हुई हैं।
- इस संग्रह में उन सभी भाषाओं की रचनाएँ शामिल हैं जिन्हें भारत ने औपचारिक रूप से शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी है, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ियों को ज्ञान के इस प्राचीन भंडार से जोड़ना है।
- यह स्थल अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- स्थान: राष्ट्रपति निलयम, सिकंदराबाद (तेलंगाना में राष्ट्रपति का आधिकारिक विश्राम स्थल)
- यहां प्रदर्शित शास्त्रीय भाषाएँ हैं: तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली।
- हाल ही में जोड़ी गई शास्त्रीय भाषाएँ (2024): मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली
- शास्त्रीय भाषा का दर्जा संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्राचीनता और विशिष्ट साहित्यिक परंपरा सहित कई मानदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है।
- राष्ट्रपति भवन के अलावा राष्ट्रपति के दो आधिकारिक विश्राम स्थल हैं: राष्ट्रपति निलयम (सिकंदराबाद) और विश्राम भवन (शिमला)।
- दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन का डिजाइन वास्तुकार एडविन लुटियंस ने तैयार किया था।

ग्राम प्रशासन के लिए नई रैंकिंग और एक चैटबॉट

खबरों में क्यों: सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों को स्वशासन प्रदान करने वाले कानून के क्रियान्वयन के आधार पर राज्यवार रैंकिंग जारी की है, साथ ही ग्राम परिषदों की सहायता के लिए एक नया चैटबॉट भी लॉन्च किया है।

मुख्य विशेषताएं:

- इस कानून के दायरे में आने वाले क्षेत्रों वाले दस राज्यों में **महाराष्ट्र** पहले स्थान पर रहा, उसके बाद मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का स्थान रहा, जबकि ओडिशा और झारखंड को सबसे निम्न प्रदर्शन करने वाली श्रेणी में रखा गया।
- रैंकिंग के साथ-साथ, निर्वाचित ग्राम प्रतिनिधियों की सहायता के लिए पंचम नामक एक नया चैटबॉट लॉन्च किया गया, जो उनके दिन-प्रतिदिन के काम के लिए आवश्यक सरल मार्गदर्शन और जानकारी तक सुगम पहुंच प्रदान करता है।
- अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश ग्राम परिषदें पहले से ही योजना और लेखा-जोखा के लिए डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करती हैं, और चैटबॉट का निर्माण बच्चों पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के सहयोग से किया गया था।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- सर्वकालिक प्रथम स्थान पर रहने वाला राज्य: महाराष्ट्र
- नया चैटबॉट लॉन्च किया गया: पंचम (पंचायत सहायता और संदेश चैटबॉट), जिसे यूनिसेफ के सहयोग से विकसित किया गया है।
- संदर्भित मूल कानून: अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत शासन का विस्तार करने वाला कानून, जो 1996 में पारित किया गया था (पेसा अधिनियम)।
- पंचायत संबंधी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है।
- 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

ज़ेहनपोरा में बौद्ध स्तूपों की खोज

खबरों में क्यों: प्रधानमंत्री ने अपने एक सार्वजनिक रेडियो संबोधन के दौरान जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के ज़ेहनपोरा में पाए गए तीन प्राचीन बौद्ध स्तूपों के बारे में बात की।

मुख्य विशेषताएं:

- इन स्तूपों के अवशेष कुषाण काल या उसके बाद के हो सकते हैं, और ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि **बौद्ध धर्म** ने कश्मीर घाटी को कितनी गहराई से प्रभावित किया था।
- प्राचीन काल में एक अलग नाम से जाना जाने वाला बारामूला, लंबे समय से व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा है, और यह खोज इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को और भी पुष्ट करती है।
- इस खोज को उजागर करने का उद्देश्य स्थानीय लोगों, विशेष रूप से युवा निवासियों को उनकी विरासत के बारे में अधिक जागरूक करना और इसके संरक्षण को प्रोत्साहित करना है, साथ ही विरासत पर्यटन में रुचि रखने वाले अधिक पर्यटकों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करना है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- यह वस्तु कहाँ मिली: ज़ेहनपोरा, बारामूला जिला, जम्मू और कश्मीर
- संभावित समय अवधि: कुषाण काल या उसके बाद
- बारामूला का पुराना नाम: वराहमुल्ला
- कुषाण काल को सामान्यतः ईसा युग की पहली और तीसरी शताब्दी के बीच माना जाता है।
- मन की बात प्रधानमंत्री का मासिक रेडियो कार्यक्रम है, जिसका पहला प्रसारण 2014 में हुआ था।
- बौद्ध धर्म के प्रसार से जुड़े उल्लेखनीय कुषाण शासक: कनिष्क, जिन्होंने चौथी बौद्ध परिषद (कुंडलवन) का आयोजन किया था।

दुर्लभ मृदा खनिजों के भंडार के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है।

खबरों में क्यों: हाल ही में आई एक वैश्विक रिपोर्ट में **भारत को** दुर्लभ मृदा खनिजों के भंडार के मामले में दुनिया में **तीसरे स्थान** पर रखा गया है, हालांकि इसका वास्तविक उत्पादन अभी भी बहुत कम है।

मुख्य विशेषताएं:

- अनुमान है कि भारत के पास विश्व के दुर्लभ मृदा खनिजों के भंडार का छह से सात प्रतिशत हिस्सा है, जो **चीन और ब्राजील** के बाद तीसरे स्थान पर है, फिर भी वैश्विक उत्पादन में इसका योगदान एक प्रतिशत से भी कम है, जिससे वास्तविक उत्पादन के मामले में यह सातवें स्थान पर है।
- भारत के अधिकांश भंडार रेत के निक्षेपों के भीतर स्थित हैं जिनमें एक रेडियोधर्मी तत्व भी मौजूद है, जो खनन और प्रसंस्करण को अधिक जटिल और अत्यधिक विनियमित बनाता है।
- भंडार और उत्पादन के बीच के इस अंतर को कम करने के लिए और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों पर केंद्रित एक विशेष मिशन शुरू किया।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- सबसे बड़े भंडार वाले देश, क्रम से: चीन, ब्राजील और फिर भारत
- खनन की प्रमुख चुनौती: भंडार रेत के निक्षेपों (मोनाजाइट रेत) में पाए जाते हैं जिनमें रेडियोधर्मी थोरियम भी मौजूद होता है।
- इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहल: राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025)
- संबंधित तथ्य: खान मंत्रालय ने भारत के लिए लगभग तीस खनिजों को महत्वपूर्ण खनिजों की सूची में शामिल किया है, जिनमें लिथियम, ग्रेफाइट और कोबाल्ट शामिल हैं।
- दुर्लभ मृदा तत्व 17 रासायनिक रूप से समान तत्वों का एक समूह है जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण और हरित प्रौद्योगिकियों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन मोटर और पवन टरबाइन में किया जाता है।
- इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (IREL) भारत में इन खनिजों के खनन और प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

उत्तर प्रदेश ने 'एक जिला एक व्यंजन' योजना शुरू की

खबरों में क्यों: उत्तर प्रदेश ने अपने पचहत्तर जिलों में से प्रत्येक के एक खास व्यंजन को भारत और विदेश दोनों जगह बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है।

मुख्य विशेषताएं:

- पहले की एक योजना के आधार पर, जिसमें प्रत्येक जिले से एक विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा दिया जाता था, यह नई पहल स्थानीय खाद्य परंपराओं को संरक्षित करने, गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने, पैकेजिंग में सुधार करने, भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने और स्थानीय खाद्य व्यवसायों को ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करने पर केंद्रित है।
- लगभग डेढ़ सौ पारंपरिक व्यंजनों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनमें से प्रत्येक जिले के लिए कम से कम एक विशिष्ट व्यंजन चुना गया है, जैसे कि आगरा की प्रसिद्ध मिठाई, लखनऊ का एक प्रसिद्ध कबाब और वाराणसी की एक लोकप्रिय मिठाई पान।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- इससे पहले यह योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना पर आधारित है।
- शामिल जिलों की संख्या: उत्तर प्रदेश के सभी पचहत्तर जिले
- उद्देश्यों में शामिल हैं: भौगोलिक संकेत (GI) टैगिंग, ऑनलाइन बिक्री की सुविधा और खाद्य पर्यटन।
- उदाहरण के तौर पर, आगरा का पेठा, लखनऊ का टुंडे कबाब और मथुरा का पेड़ा।
- ODOP योजना को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में शुरू किया गया था और बाद में इसे केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया।
- उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो उस दिन की याद दिलाता है जब 1950 में राज्य का नाम बदलकर संयुक्त प्रान्त से उत्तर प्रदेश रखा गया था।

विशाखापत्तनम में लाइटहाउस महोत्सव का आयोजन हुआ

खबरों में क्यों: ऐतिहासिक विशाखापत्तनम लाइटहाउस के आसपास एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया, जो पुराने लाइटहाउसों को पर्यटक आकर्षणों में बदलने की व्यापक योजना का हिस्सा है।

मुख्य विशेषताएं:

- जहाजरानी और बंदरगाहों के लिए जिम्मेदार मंत्रालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में आंध्र प्रदेश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थानीय लोक संगीत, नृत्य और कला का प्रदर्शन किया गया।
- अधिकारियों की योजना प्रकाशस्तंभों के आसपास संग्रहालय, बच्चों के पार्क और अन्य मनोरंजक सुविधाएं बनाने की है ताकि उन्हें आकर्षक पर्यटक स्थल बनाया जा सके।
- विशाखापत्तनम लाइटहाउस बंगाल की खाड़ी के नज़ारे वाली एक पहाड़ी पर स्थित है और कई वर्षों से जहाजों को सुरक्षित मार्ग दिखाता आ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर, सरकार की योजना इसी तरह से पचहत्तर ऐतिहासिक लाइटहाउसों को विकसित करने की है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- संबंधित मंत्रालय: बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय
- विशाखापत्तनम प्रकाशस्तंभ का स्थान: बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी पर।
- लाइटहाउस पर्यटन विकास के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य: पचहत्तर ऐतिहासिक लाइटहाउस
- भारत में प्रकाशस्तंभों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार निकाय प्रकाशस्तंभ एवं प्रकाशयान महानिदेशालय (DGLL) है।
- विशाखापत्तनम (विजाग) में भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय स्थित है।

- यह पहल बंदरगाह आधारित विकास के व्यापक सागरमाला कार्यक्रम का समर्थन करती है।

संपूर्णता अभियान अभियान का दूसरा चरण

खबरों में क्यों?: सरकार के नीतिगत विचार-मंथन तंत्र ने देश के सबसे पिछड़े जिलों और ब्लॉकों में विकास संकेतकों के एक समूह को पूरी तरह से हासिल करने के उद्देश्य से **तीन महीने का अभियान** शुरू किया है।

मुख्य विशेषताएं:

- इस अभियान का लक्ष्य देशभर के आकांक्षी जिलों में पांच प्रमुख संकेतकों और **आकांक्षी ब्लॉकों** में छह संकेतकों की पूर्ण उपलब्धि हासिल करना है।
- ब्लॉकों के लिए जिन संकेतकों पर नज़र रखी जाती है, उनमें नियमित रूप से पूरक पोषण प्राप्त करने वाले छोटे बच्चों का हिस्सा और स्थानीय बाल देखभाल केंद्रों में उनके विकास की निगरानी कितनी अच्छी तरह से की जा रही है, शामिल हैं।
- इसका समग्र लक्ष्य उन क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं में शेष कमियों को दूर करना है जो ऐतिहासिक रूप से देश के बाकी हिस्सों से पीछे रहे हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- आरंभकर्ता संस्था: नीति आयोग
- अभियान का नाम: संपूर्णता अभियान, द्वितीय संस्करण
- कवरेज: आकांक्षी जिलों के लिए पांच संकेतक, आकांक्षी ब्लॉकों के लिए छह संकेतक
- संदर्भित संबंधित योजना: एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) कार्यक्रम, जो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित होता है।
- भारत के सबसे पिछड़े जिलों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को बेहतर बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था।
- ब्लॉक स्तर पर इसी तरह की एक पहल, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, 2023 में शुरू की गई थी।

भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बीच सांस्कृतिक सम्मेलन

खबरों में क्यों?: भारत के प्रमुख बंदरगाहों के श्रमिक और कलाकार नृत्य, नाटक और संगीत की विशेषता वाली एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता के लिए ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर एकत्रित हुए।

मुख्य विशेषताएं:

- **पारादीप बंदरगाह** प्राधिकरण और प्रमुख बंदरगाहों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक खेल निकाय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित चार दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के नौ बंदरगाहों से लगभग दो सौ कलाकार एक साथ आए, जिसका उद्देश्य बंदरगाह समुदायों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव की भावना का निर्माण करना था।
- विभिन्न श्रेणियों में हुई प्रतियोगिताओं के बाद, कोलकाता स्थित बंदरगाह प्राधिकरण को समग्र विजेता घोषित किया गया, जबकि मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण उपविजेता रहा और कांडला और कोचीन बंदरगाह प्राधिकरणों ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान साझा किया।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- स्थान: पारादीप बंदरगाह, ओडिशा
- भाग लेने वाले प्रमुख बंदरगाहों की संख्या: नौ
- कुल मिलाकर विजेता बंदरगाह प्राधिकरण: कोलकाता स्थित, जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है (पूर्व में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट)।
- आयोजक: पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण और प्रमुख बंदरगाह खेल नियंत्रण बोर्ड
- भारत में वर्तमान में बारह प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनका प्रशासन प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अंतर्गत किया जाता है।

- बंगाल की खाड़ी पर ओडिशा में स्थित पारादीप बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और कोयला और लौह अयस्क निर्यात का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।

भारत की पहली खुली समुद्री मत्स्य पालन परियोजना

खबरों में क्यों: भारत ने खुले समुद्री जल में अपनी पहली मत्स्य पालन परियोजना शुरू की है, जो **अंडमान सागर** में स्थित है, जिसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों के उपयोग और स्थानीय मछुआरा समुदायों दोनों का समर्थन करना है।

मुख्य विशेषताएं:

- **अंडमान की राजधानी** के पास **नॉर्थ बे** नामक क्षेत्र में स्थापित इस पायलट प्रोजेक्ट में उन्नत पिंजरा आधारित तकनीक का उपयोग करके सीबास और कोबिया जैसी मछली प्रजातियों के साथ-साथ समुद्री शैवाल का पालन-पोषण खुले पानी में किया जाता है, न कि तट के करीब।
- इसका लक्ष्य समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना, समुद्री भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करना और तटीय मत्स्यन समुदायों को आय का अधिक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करना है।
- यह परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, एक राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और स्थानीय द्वीप प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- स्थान: उत्तरी खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी (श्री विजयपुरम) के निकट
- इसमें शामिल निकाय: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT, चेन्नई) और स्थानीय द्वीप प्रशासन
- जिन प्रजातियों की खेती की जा रही है: सीबास, कोबिया और समुद्री शैवाल
- यह जिस व्यापक आर्थिक विषय का समर्थन करता है, वह है: महासागर आधारित, या नीली अर्थव्यवस्था।
- भारत में मत्स्य पालन विकास को समर्थन देने वाली केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) है।
- खुले समुद्र में पिंजरे बनाकर मत्स्यन, जिसे समुद्री कृषि भी कहा जाता है, को तटवर्ती मछली भंडार को कम किए बिना मछली उत्पादन बढ़ाने के तरीके के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

Understand UPSC

वैश्विक चर्चा

विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक "संवाद की भावना" पर केंद्रित है।

खबरों में क्यों: विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक दावोस में आयोजित की गई। इसमें "संवाद की भावना" विषय के तहत रिकॉर्ड संख्या में विश्व नेता एकत्रित हुए। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक तनाव के इस दौर में विश्वास का पुनर्निर्माण करना और सहयोग को प्रोत्साहित करना था।

मुख्य विशेषताएं:

- चर्चा में पांच मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया: विभाजित दुनिया में भू-राजनीतिक सहयोग को मजबूत करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के नए तरीके खोजना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदारी से उपयोग करना, आर्थिक विकास को जलवायु और पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ संतुलित करना और शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करना।
- इस बैठक में लगभग 65 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इनमें राष्ट्रपति ट्रंप, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेन्स्की जैसे महत्वपूर्ण नेता शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जैसे वैश्विक नेता भी उपस्थित थे। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और एनवीडिया के जेन्सेन हुआंग जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गज भी मौजूद थे।
- भारत ने 'मेक इन इंडिया 2.0' और अपने डिजिटल आधारभूत अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भेजा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों ने निवेश आकर्षित करने के लिए अपने-अपने पवेलियन स्थापित किए। 100 से अधिक भारतीय कंपनियों के सीईओ ने भी इसमें भाग लिया।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- संस्करण: विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक
- विषय: "संवाद की भावना"
- पांच प्रमुख क्षेत्र: भू-राजनीतिक सहयोग, आर्थिक विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवाचार, जलवायु और प्रकृति, शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य
- लगभग 65 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया।
- जिन भारतीय राज्यों में पवेलियन होंगे: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक
- विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय: कोलोनी, स्विट्जरलैंड
- WEF मुख्य रूप से दावोस में आयोजित होने वाली अपनी वार्षिक बैठक के लिए जाना जाता है।

भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना लोगो, थीम और वेबसाइट जारी की।

खबरों में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मकर संक्रांति के अवसर पर भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए आधिकारिक लोगो, थीम और वेबसाइट का शुभारंभ किया।

मुख्य विशेषताएं:

- यह लोगो पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का संयोजन है। इसकी रंगीन पंखुड़ियाँ ब्रिक्स सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि केंद्र में स्थित नमस्ते का चिन्ह आपसी सम्मान और सहयोग को दर्शाता है।
- "लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" विषय भारत के समावेशी विकास, नवाचार और दीर्घकालिक सहयोग पर केंद्रित दृष्टिकोण को उजागर करता है।
- ब्रिक्स का गठन 2006 में हुआ था और इसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था। इसके मूल सदस्य ब्राजील, रूस, भारत और चीन थे। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इस समूह में शामिल हुआ।
- हाल के वर्षों में इस समूह का विस्तार हुआ है। मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात 2024 में सदस्य बने, जबकि इंडोनेशिया 2025 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इस विस्तार ने विकासशील देशों के लिए एक मंच के रूप में ब्रिक्स को मजबूत किया है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- आधिकारिक वेबसाइट: brics2026.gov.in
- विषय: "लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण"
- ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी।
- पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: 2009
- मूल सदस्य: ब्राजील, रूस, भारत, चीन
- दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ।
- नए सदस्य: मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात (2024), इंडोनेशिया (2025)
- ब्रिक्स बैंक: न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB), जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी और जिसका मुख्यालय शंघाई में है।
- भारत इससे पहले नई दिल्ली (2012), गोवा (2016) में और 2021 में वर्चुअल रूप से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है।

पैक्स सिलिका: चिप और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पर एक नया अमेरिकी नेतृत्व वाला गठबंधन

खबरों में क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। यह एक नया अमेरिकी नेतृत्व वाला गठबंधन है जिसे सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है।

मुख्य विशेषताएं:

- पैक्स सिलिका उन देशों को एक साथ लाता है जिन्हें अमेरिका भविष्य की प्रमुख प्रौद्योगिकियों में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए विश्वसनीय साझेदार मानता है। अमेरिका ने भारत को उसके विशाल इंजीनियरिंग कार्यबल और बढ़ते सेमीकंडक्टर उद्योग के कारण एक "अत्यावश्यक साझेदार" बताया है।
- इस गठबंधन के मूल सदस्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, नीदरलैंड, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया हैं। कतर बाद में इस समूह में शामिल हुआ।
- भारत के लिए पैक्स सिलिका से जुड़ने से उन्नत चिप डिजाइन और विनिर्माण प्रौद्योगिकी तक पहुंच मिल सकती है। इससे भारत के सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों में विदेशी निवेश भी बढ़ सकता है और दुर्लभ खनिजों तक पहुंच में सुधार हो सकता है, जो स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- पैक्स सिलिका, सेमीकंडक्टर, AI और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाला एक गठबंधन है।
- भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया है और अमेरिका द्वारा इसे "अत्यावश्यक भागीदार" कहा गया है।
- मूल सदस्य: अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, नीदरलैंड, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया।
- कतर बाद में शामिल हुआ।
- संबंधित भारतीय कार्यक्रम: **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)**।
- मुख्य उद्देश्य: महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए चीन पर निर्भरता कम करना।
- कनाडा, यूरोपीय संघ, OECD और ताइवान पैक्स सिलिका में शामिल नहीं हुए हैं।

भारत और यूरोपीय संघ ने बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया, जिसे "सभी समझौतों की जननी" कहा जाता है।

खबरों में क्यों: लगभग बीस वर्षों की बातचीत के बाद, भारत और यूरोपीय संघ ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान अपने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के पूरा होने की घोषणा की। व्यापार जगत में इस समझौते को "सभी समझौतों की जननी" कहा जा रहा है।

मुख्य विशेषताएं:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- यह समझौता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेतकों को समाहित करता है। भारत और यूरोपीय संघ मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग एक चौथाई हिस्सा और लगभग दो अरब लोगों का बाजार बनाते हैं।

- समझौते के तहत, यूरोपीय संघ भारत के लगभग **99.5%** निर्यात पर शुल्क हटा देगा। भारत अगले दस वर्षों में यूरोपीय संघ को होने वाले लगभग **97.5%** निर्यात पर शुल्क धीरे-धीरे कम करेगा।
- इस समझौते की एक प्रमुख विशेषता **ऑटो और वाइन** डील है, जो यूरोपीय कारों और वाइन पर आयात शुल्क को कम करती है।
- कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण जैसे भारतीय क्षेत्रों को यूरोपीय बाजार में तत्काल शून्य शुल्क पर प्रवेश मिल जाएगा। इससे भारत के निर्यात में सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि, भारतीय निर्यातकों को अभी भी यूरोपीय संघ के सख्त पर्यावरण और श्रम मानकों का पालन करना होगा। इस समझौते को लागू होने से पहले यूरोपीय संसद और भारतीय मंत्रिमंडल की मंजूरी भी आवश्यक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में **16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन** के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए।
- इसे **"सभी समझौतों की जननी"** के रूप में जाना जाता है।
- यूरोपीय संघ में भारत के लगभग **99.5%** निर्यात पर शून्य टैरिफ लगेगा।
- भारत दस वर्षों में यूरोपीय संघ के 97.5% निर्यात पर टैरिफ कम करेगा।
- जिन क्षेत्रों को तत्काल लाभ मिलेगा: वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण।
- प्रमुख चुनौती: **कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)**।
- भारत ने ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशस और EFTA ब्लॉक के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं।

क्वाड के राजदूतों ने बीजिंग में एक दुर्लभ सार्वजनिक बैठक आयोजित की

खबरों में क्यों: क्वाड संघ के चार देशों - भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया - के राजदूतों ने बीजिंग स्थित अमेरिकी दूतावास में एक दुर्लभ सार्वजनिक बैठक की। इस बैठक को चीन के लिए एक महत्वपूर्ण राजनयिक संदेश के रूप में देखा गया।

मुख्य विशेषताएं:

- भारत के राजदूत **प्रदीप कुमार रावत** इस बैठक में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राजदूतों के साथ शामिल हुए।
- अमेरिकी राजदूत डेविड पड्यू ने क्वाड को एक **"सकारात्मक शक्ति"** बताया जो एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक का समर्थन करती है। उन्होंने यह भी कहा कि चारों देशों के बीच सहयोग मजबूत और स्थिर बना हुआ है।
- यह बैठक उस समय हुई जब चीन दक्षिण चीन सागर और ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास कर रहा था। इस समय को देखते हुए, बीजिंग में हुई इस सार्वजनिक बैठक को क्वाड सदस्यों के बीच एकता के स्पष्ट संकेत के रूप में देखा गया।
- चीन अक्सर क्वाड की आलोचना करता रहा है, इसे **"एशियाई नाटो"** कहता रहा है और इस पर गुटबाजी को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि, क्वाड के सदस्य देश लगातार यह कहते रहे हैं कि यह समूह किसी विशेष देश के खिलाफ निर्देशित नहीं है और एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- क्वाड के सदस्य: भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया।
- भारत के प्रतिनिधि: **प्रदीप कुमार रावत**।
- बैठक स्थल: **अमेरिकी दूतावास, बीजिंग, चीन**।
- पूरा नाम: **चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद (QSD)**।
- जापान के प्रधानमंत्री **शिंजो आबे** द्वारा **2007** में प्रस्तावित।
- लगभग एक दशक बाद **2017** में इसे पुनर्जीवित किया गया।
- पहला वर्चुअल लीडर्स समिट **2021** में आयोजित किया गया।
- चीन अक्सर क्वाड को **"एशियाई नाटो"** कहता है।

ट्रम्प द्वारा गठित शांति बोर्ड एक नए वैश्विक निकाय के रूप में आकार ले रहा है।

खबरों में क्यों: राष्ट्रपति ट्रम्प के समर्थन से 'बोर्ड ऑफ पीस' नामक एक नए निकाय का आधिकारिक तौर पर गठन किया गया है, जिसका काम इजरायल-हमास संघर्ष के बाद गाजा में युद्धविराम, पुनर्निर्माण और शासन की देखरेख करना है। भारत भी उन देशों में शामिल है जिन्हें इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

मुख्य विशेषताएं:

- इस बोर्ड का गठन **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** के प्रस्ताव के तहत किया गया था और दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य गाजा में शांति स्थापना और पुनर्निर्माण में सहयोग करना है। इसकी जिम्मेदारियों में हमास को निरस्त करना, नई फिलिस्तीनी पुलिस बल को प्रशिक्षण देना और **गाजा प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति (NCAG)** के माध्यम से गाजा के अस्थायी प्रशासन की निगरानी करना शामिल है।
- डोनाल्ड ट्रम्प को बोर्ड का **आजीवन अध्यक्ष** नामित किया गया है। कार्यकारी परिषद में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, जेरेड कुशनर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो शामिल हैं।
- स्थायी सदस्यता चाहने वाले देशों को गाजा के पुनर्निर्माण के लिए **एक अरब अमेरिकी डॉलर** का योगदान देना होगा। योगदान न देने वाले देश केवल तीन साल के लिए ही शामिल हो सकते हैं। अब तक लगभग 36 देश शामिल हो चुके हैं, जबकि कुछ प्रमुख यूरोपीय देश इससे बाहर रहे हैं। कनाडा को बाद में बोर्ड से हटा दिया गया था।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- वैधानिक आधार: **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2803 (2025)**
- गाजा का अंतरिम प्रशासनिक निकाय: **NCAG**
- आजीवन अध्यक्ष: **डोनाल्ड ट्रम्प**
- स्थायी सदस्यता शुल्क: **1 बिलियन अमेरिकी डॉलर**
- सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया।

खबरों में क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका ने कराकस समेत वेनेजुएला पर हवाई हमले किए और बाद में राष्ट्रपति **निकोलस मादुरो** और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई की वैधता को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई है।

मुख्य विशेषताएं:

- '**एब्सोल्यूट रिजॉल्व**' नामक यह अभियान राष्ट्रपति ट्रम्प के आदेश पर शुरू किया गया था। गिरफ्तार होने और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क ले जाए जाने से पहले मादुरो ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी।
- अमेरिका ने कहा कि यह अभियान मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से लड़ने और लोकतंत्र को बहाल करने के उद्देश्य से चलाया गया था। रूस और चीन ने इसकी आलोचना करते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया।
- वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति **डेल्सी रोड्रिगेज** कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गईं। विपक्षी नेता **मारिया कोरिना मचाडो** एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती के रूप में उभरी हैं। भारत ने राष्ट्रीय संप्रभुता के सम्मान और शांतिपूर्ण कूटनीति का आह्वान किया, साथ ही चिंता व्यक्त की कि वेनेजुएला में अस्थिरता से वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- ऑपरेशन: **एब्सोल्यूट रिजॉल्व**
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** द्वारा बुलाई गई आपातकालीन बैठक
- राजधानी: **काराकास**
- मुद्रा: **बोलिवर**
- दुनिया में तेल का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार
- सबसे ऊँचा जलप्रपात: **एंजेल फॉल्स**

- मुख्य नदी: ओरिनोको
- सीमाएँ: कैरेबियन सागर, गुयाना, ब्राज़ील, कोलंबिया
- संबंधित संयुक्त राष्ट्र चार्टर प्रावधान: अनुच्छेद 2(4)

दशकों लंबी कानूनी लड़ाई के बाद चागोस द्वीप समूह का स्वामित्व बदल गया।

खबरों में क्यों: ब्रिटेन ने चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरीशस को हस्तांतरित करने पर सहमति जताई है, जबकि **डिएगो गार्सिया** सैन्य अड्डे को अगले 99 वर्षों तक ब्रिटेन के पास ही रखा जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा समझौते की आलोचना के बाद यह मुद्दा खबरों में बना रहा।

मुख्य विशेषताएं:

- मॉरीशस के स्वतंत्र होने से पहले, 1965 में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को मॉरीशस से अलग कर दिया था। 1960 और 1970 के दशक के दौरान, स्थानीय लोगों को विस्थापित करके **डिएगो गार्सिया** सैन्य अड्डा बनाया गया, जिसका उपयोग ब्रिटेन और अमेरिका संयुक्त रूप से करते हैं।
- मॉरीशस ने तर्क दिया कि द्वीपों की वापसी के बिना उसकी स्वतंत्रता अधूरी है। 2019 में, **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)** ने फैसला सुनाया कि ब्रिटेन का निरंतर नियंत्रण गैरकानूनी था।
- 2024 के समझौते के तहत, ब्रिटेन ने मॉरीशस की संप्रभुता को मान्यता दी, लेकिन सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए **डिएगो गार्सिया** बेस पर अपना नियंत्रण अगले 99 वर्षों तक बरकरार रखा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- संप्रभुता का हस्तांतरण: **ब्रिटेन से मॉरीशस को**
- लगभग **60 द्वीप मिलकर 7 एटोल** बनाते हैं।
- सबसे बड़ा द्वीप: **डिएगो गार्सिया**
- ICJ की सलाहकारी राय: **2019**
- **डिएगो गार्सिया** पट्टा: **99 वर्ष**
- यह मालदीव के दक्षिण में, **हिंद महासागर** में स्थित है।

जर्मन चांसलर मर्ज़ ने भारत की अपनी पहली यात्रा की।

खबरों में क्यों: जर्मन चांसलर **फ्रेडरिक मर्ज़** ने पदभार संभालने के बाद पहली बार भारत का दौरा किया। इस दौरे के दौरान दोनों देशों ने **19 समझौतों** पर हस्ताक्षर किए और **8 महत्वपूर्ण घोषणाएं** कीं।

मुख्य विशेषताएं:

- इस यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से हुई, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने चांसलर मर्ज़ का स्वागत किया। उन्होंने **साबरमती आश्रम** का दौरा किया, जहां मर्ज़ ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और चरखा चलाने का प्रयास किया।
- दोनों देशों ने **P75I पनडुब्बी परियोजना** को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत जर्मनी की **थिसेनक्रूप मरीन सिस्टम्स**, **मजगांव डॉक** के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए छह पनडुब्बियों का निर्माण करेगी।
- जर्मनी ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन कार्यक्रम और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को समर्थन देने पर भी सहमति जताई। दोनों देशों ने भारतीय पेशेवरों के लिए वीजा नियमों को सरल बनाने और कौशल विकास सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- हस्ताक्षरित समझौते: **19 समझौता ज्ञापन**
- रक्षा परियोजना: **P75I**
- जर्मन साझेदार: **थिसेनक्रूप मरीन सिस्टम्स**
- भारतीय साझेदार: **मजगांव डॉक**
- जर्मन विकास बैंक: **KfW**

- मनाया गया: रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष और राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष
- राजधानी: बर्लिन
- मुद्रा: यूरो

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पांच नए अस्थाई सदस्य शामिल हुए

खबरों में क्यों: बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लातविया और लाइबेरिया ने 1 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों के रूप में अपना दो साल का कार्यकाल शुरू किया।

मुख्य विशेषताएं:

- इन देशों का चुनाव पिछले वर्ष जून में हुआ था और इन्होंने उन निवर्तमान सदस्यों का स्थान लिया था जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया था।
- लातविया का चुनाव ऐतिहासिक है क्योंकि यह सुरक्षा परिषद में देश की पहली सदस्यता है।
- संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सीटों को विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के बीच विभाजित किया गया है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- नए सदस्य (2026-27): बहरीन, कोलंबिया, DR कांगो, लातविया, लाइबेरिया
- प्रतिस्थापित: अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया
- स्थायी सदस्य (P5): अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन
- अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होता है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य: 15 (5 स्थायी + 10 अस्थायी)

एक नए सूचकांक में देशों को "जिम्मेदारी" के आधार पर स्थान दिया गया है और भारत शीर्ष 20 में शामिल हो गया है।

खबरों में क्यों: हाल ही में जारी किए गए रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI) 2026 में भारत 154 देशों में 16वें स्थान पर रहा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन दोनों से बेहतर प्रदर्शन है।

मुख्य विशेषताएं:

- इस सूचकांक को विश्व बौद्धिक फाउंडेशन (WIF) ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और IIM मुंबई के साथ मिलकर विकसित किया था। इसका शुभारंभ पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने किया था।
- यह रैंकिंग तीन मुख्य क्षेत्रों पर आधारित है:
 - आंतरिक उत्तरदायित्व (शासन, सामाजिक न्याय और नागरिक कल्याण)
 - पर्यावरण संबंधी उत्तरदायित्व (जलवायु कार्रवाई और संसाधन प्रबंधन)
 - बाह्य उत्तरदायित्व (वैश्विक शांति और सहयोग में योगदान)
- सिंगापुर पहले स्थान पर रहा, उसके बाद स्विट्जरलैंड और डेनमार्क का स्थान रहा। भारत का अच्छा प्रदर्शन स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संबंधी प्रयासों और नागरिक-केंद्रित शासन में सुधार से जुड़ा था।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- सूचकांक: जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक (RNI) 2026
- WIF, JNU और IIM मुंबई द्वारा विकसित
- राम नाथ कोविंद द्वारा आरंभ किया गया
- रैंकिंग वाले देश: 154
- तीन स्तंभ: आंतरिक, पर्यावरणीय और बाह्य उत्तरदायित्व

- शीर्ष तीन देश: सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क
- भारत 16वें स्थान पर रहा।
- अमेरिका 66वें स्थान पर, चीन 68वें स्थान पर रहा।

डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में नाटो से जुड़े एक बड़े सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किया।

खबरों में क्यों: डेनमार्क आर्कटिक क्षेत्र में नाटो की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रीनलैंड में आयोजित एक बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस का नेतृत्व कर रहा है।

मुख्य विशेषताएं:

- इस अभ्यास में फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड, आइसलैंड और बेल्जियम के सैनिक शामिल हैं। अतिरिक्त सैनिक, वायु रक्षा पोत और F-35 लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए हैं।
- इस अभ्यास को डेनमार्क द्वारा ग्रीनलैंड पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, खासकर राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा द्वीप को हासिल करने में बार-बार रुचि व्यक्त करने के बाद। यह ऐसे समय में भी हो रहा है जब आर्कटिक में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- अभ्यास: ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस
- अग्रणी देश: डेनमार्क
- मेजबान क्षेत्र: ग्रीनलैंड
- मुख्य तैनाती क्षेत्र: नुउक और कंगेरलुसुआक
- प्रतिभागी देश: फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम
- संबंधित मुद्दा: ग्रीनलैंड की संप्रभुता और आर्कटिक सुरक्षा

भारत ने राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और कार्यकारी अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी की।

खबरों में क्यों: भारत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (CSPOC) की मेजबानी की।

मुख्य विशेषताएं:

- इस सम्मेलन में राष्ट्रमंडल के 42 देशों के 61 स्पीकरों और कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया।
- चर्चाओं में विधायिकाओं में पारदर्शिता में सुधार लाने, समावेशी निर्णय लेने को प्रोत्साहित करने और सामान्य लोकतांत्रिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- भारत ने अपनी संसदीय प्रणाली और डिजिटल शासन में हासिल की गई उपलब्धियों का प्रदर्शन किया, साथ ही अन्य राष्ट्रमंडल देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- सम्मेलन: CSPOC
- संस्करण: 28वां
- अध्यक्ष: ओम बिरला
- प्रतिभागी: 42 देशों के 61 स्पीकर
- स्थापना: 1969 (कनाडा की पहल पर)
- भारत ने इससे पहले 1971, 1986 और 2010 में इसकी मेजबानी की थी।
- अगला सम्मेलन: लंदन, यूनाइटेड किंगडम (2028)